भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 411
दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-कनाडा संबंध

411. **डा. जॉन ब्रिटासः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कनाडा ने भारत को साइबर थ्रैट ऐडवर्सरी घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन बयानों का प्रत्युत्तर देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कनाडा में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाकर साइबर निगरानी या अन्य प्रकार की निगरानी करने के कोई मामले हैं; और

(ड.) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]

(क) से (ग) जी, हाँ। कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ने 30 अक्टूबर 2024 को जारी अपनी द्विवार्षिक राष्ट्रीय साइबर खतरा आकलन (एनसीटीए) रिपोर्ट में 2025–2026 की अवधि के लिए भारत को "धारा 1 – राष्ट्र विरोधियों से साइबर खतरा" के अंतर्गत रखा है। विदेश मंत्रालय ने 02 नवंबर 2024 को रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह भारत के साथ संबंधों के प्रति कनाडा के नकारात्मक दृष्टिकोण का एक और उदाहरण है। अन्य अवसरों की तरह, बिना किसी प्रमाण के भारत पर आरोप लगाए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। हाल ही में, वैंकूवर स्थित भारतीय कोंसलावास के कोंसली अधिकारियों को कनाडा के प्रधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि उनकी ऑडियो और वीडियो निगरानी की जा रही है और यह अभी भी जारी हैं तथा उनके निजी पत्राचारों की भी निगरानी की जा रही है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर नई दिल्ली में कनाडाई उच्चायोग के समक्ष 02 नवंबर 2024 के अपने नोट वर्बाल के माध्यम से कड़ा विरोध दर्ज कराया क्योंकि ये कार्य सभी राजनयिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया को अपनी साप्ताहिक ब्रीफिंग में यह भी कहा कि: "तकनीकी पहलुओं का हवाला देकर, कनाडा सरकार इस तथ्य को उचित नहीं ठहरा सकती कि वह उत्पीड़न कर रही है और धमका रही है। हमारे राजनयिक और कोंसलावास के कर्मचारी पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं। कनाडा सरकार की यह कार्रवाई स्थिति को और खराब करती है और यह स्थापित राजनयिक मानदंडों और प्रथाओं के अनुरूप नहीं है।"
कनाडा में भारतीय राजनयिकों की संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रश्न पर, भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कनाडाई पक्ष के साथ लगातार संपर्क में है कि हमारे राजनयिक कर्मियों और संपत्तियों को हर समय पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।

*****